माननीय न्यायमूर्ति वी. के. झांजी के समक्ष,

एम/एस. जे. आई. पी. आई. आर. मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स जैन इंडस्ट्रीज, रोहतक और अन्य-उत्तरदाता

1993 की सिविल संशोधन सं **3101**

12 अक्टूबर, **1993**

विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम (1963 का 47)- धारा 14 (1) (सी) और 41 (सी) -डीलरशिप को गलत तरीके से समाप्त किया गया -याचिकाकर्ता को डीलरशिप को समाप्त करने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया-अनुमत-विवादित आदेश को अलग रखा गया-आयोजित, डीलर केवल हर्जाने का दावा करने का हकदार है और बहाली का नहीं -निषेधाज्ञा के किसी भी आदेश को विक्रेता की समाप्ति को रोकने के लिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रारंभिक चरण में डिक्री मुकदमा होगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ता-कंपनी ने डीलरशिप को समाप्त करने का निर्णय लिया, तो अदालतों के लिए यह प्रतिबंध का आदेश पारित करने के लिए खुला नहीं था क्योंकि यह एक समझौते को लागू करने के बराबर होगा जो लागू करने योग्य नहीं था। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस बात की सराहना नहीं की है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत, कुछ अनुबंध प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिनमें से एक, खंड (सी) एक अनुबंध है जो अपनी प्रकृति में निर्धारणीय है। 'निर्धारणीय' शब्द का अर्थ है जिसे समाप्त किया जा सकता है। निश्चय का अर्थ है चीज़ का अंत करना। खंड (ग) यह अधिनियमित करता है कि अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यदि यह अपनी प्रकृति में निर्धारित करने योग्य है। विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41, खंड (ई) में यह प्रावधान है कि किसी अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, जिसके निष्पादन को विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, यदि वादी एक अनुबंध को लागू नहीं कर सकता है जो निर्धारित करने योग्य है, तो प्रतिवादी को इसे समाप्त नहीं करने से कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए कि डीलरशिप को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था, तब भी कानूनी रूप से, डीलर हर्जाने का दावा कर सकता है लेकिन किसी भी मामले में डीलरशिप को बहाल नहीं किया जा सकता है। डीलरशिप स्वाभाविक रूप से कानून में समाप्त करने योग्य है और आम तौर पर डीलरशिप को समाप्त करने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्रभाव प्रारंभिक चरण में मुकदमा होगा।

(पैरा 6) याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत सरीन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन।

अशोक अग्रवाल, सुभाष गोयल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता। प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता और विपुन मित्तल, अधिवक्ता।

निर्णय

(1) यह आदेश (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक के खिलाफ प्रतिवादी का सिविल संशोधन है, जिसके तहत वरिष्ठ उप न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित एकतरफा और अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक सीमित कंपनी है जो जयपुर, राजस्थान में विद्युत मीटर के निर्माण में लगी हुई है। 1992 में, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता कंपनी से संपर्क किया और उससे वादी-प्रतिवादी नं. 1 हरियाणा राज्य के लिए इसके डीलर के रूप में 13 अक्टूबर, 1992 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता कंपनी ने हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों के लिए प्रतिवादी-फर्म को अपने डीलर के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया। यह डीलरशिप अस्थायी थी और केवल 31 मार्च, 1993 तक वैध थी। याचिकाकर्ता-कंपनी ने 10 जून, 1993 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी-फर्म को सूचित किया कि नियुक्ति पत्र के संदर्भ में डीलरशिप को समाप्त कर दिया गया है। लगभग दो महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद, प्रत्यर्थी-फर्म ने याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमे में, उस पत्र दिनांक 10 जून के प्रभाव से घोषणा की मांग की गई थी। 1993 में डीलरशिप को समाप्त करना पूरी तरह से अवैध है, अधिकार क्षेत्र के बिना और शून्य है और आगे की घोषणा के लिए कि प्रत्यर्थी-फर्म के नाम पर दी गई ऊर्जा मीटरों के लिए डीलरशिप अभी भी मौजूद है और जारी है और जब तक कि कोई गलती या नियुक्ति पत्र का उल्लंघन प्रत्यर्थी-फर्म द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक समाप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। याचिकाकर्ता-कंपनी को इलेक्ट्रिक मीटरों के संबंध में डीलरशिप को समाप्त करने और नियमित भुगतान के खिलाफ विचारशील-फर्म द्वारा इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक निषेधाज्ञा भी मांगी गई थी। याचिकाकर्ता-कंपनी को 31 अगस्त, 1993 तक प्रत्यर्थी-फर्म को 16,900 मीटर की आपूर्ति करने और भविष्य में भुगतान के बदले हर महीने 3,000 ऊर्जा मीटर की आपूर्ति करने का निर्देश देने के लिए भी एक और राहत मांगी गई। प्रत्यर्थी-फर्म ने आरोप लगाया कि उसने 31 मार्च, 1993 तक 38,000 मीटर से अधिक के लिए ऑर्डर दिए थे और अब तक केवल 14,000 मीटर की आपूर्ति की गई थी और इस प्रकार 24,000 मीटर की आपूर्ति अभी भी लंबित थी। प्रत्यर्थी-फर्म ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता-कंपनी उन्हें आपूर्ति नहीं कर रही थी, इसलिए प्रत्यर्थी-फर्म को ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति न होने के कारण भारी नुकसान हो रहा था। मुकदमे के साथ, अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिस पर निचली अदालत ने उसी तारीख को एकतरफा आदेश पारित किया था जिस दिन मुकदमा पेश किया गया था। आदेश का प्रभाव यह था कि याचिकाकर्ता-कंपनी को विचाराधीन-फर्म ट्रायल कोर्ट को बिजली मीटरों की आपूर्ति रोकने से रोक दिया गया था और इसे प्रतिवादी-फर्म की डीलरशिप को समाप्त करने के रूप में मान्यता देने से रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता-कंपनी को भुगतान के बदले 16,900 मीटर की आपूर्ति करने और 13 अक्टूबर, 1992 के नियुक्ति पत्र के संदर्भ में 3,000 मीटर प्रति माह, एकल चरण या तीन चरण की आपूर्ति जारी रखने का भी निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता-कंपनी ने एकतरफा आदेश से व्यथित महसूस करते हुए अपील की जिसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक ने खारिज कर दिया। यह आदेश इस नागरिक संशोधन में आक्षेपित है।

(3) श्री एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता-कंपनी के वकील ने आदेश का विरोध करते हुए दिनांक 13 अक्टूबर, 1992 के पत्र के विभिन्न खंडों का संदर्भ दिया, जिसमें प्रतिवादी फर्म को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था और तर्क दिया गया था कि एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि रोहतक की अदालतों को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि समझौते के तहत पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की थी कि विवाद के मामले में, यह जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

(4) उत्तर में, प्रत्यर्थी-फर्म के वकील, श्री अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डीलरशिप के पत्र के तहत, समाप्ति से पहले 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक था और यह नहीं दिया गया था, नीचे दिए गए न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा देने में सही थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-फर्म के निष्पादन के संबंध में समीक्षा, यदि बिल्कुल भी आवश्यक थी, तो वह 31 मार्च, 1993 से पहले की जानी चाहिए थी, जब समझौता समाप्त होना था। उनका सटीक तर्क यह था कि 31 मार्च, 1993 के बाद, प्रत्यर्थी-फर्म ने कुछ आपूर्ति करने के बाद, उनकी एजेंसी को समाप्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह समझौते के खंड 1 का उल्लंघन करेगा जिसमें 30 दिनों के नोटिस का प्रावधान था।

(5) इससे पहले कि मैं पक्षकारों के विद्वत वकील की संबंधित दलीलों और विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश पर विचार करूं, जिन्होंने अपील में विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की थी, मैं अवश्य कहूंगा कि वरिष्ठ उप न्यायाधीश, रोहतक एकतरफा आदेश पारित करने में न्यायोचित नहीं था। डीलरशिप को समाप्त कर दिया गया था-दिनांक 10 जून, 1993 का पत्र। मुकदमा 17 अगस्त, 1993 को दायर किया गया था डीलरशिप को समाप्त करने वाले पत्र की प्राप्ति के दो महीने बाद। वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने 17 अगस्त, 1993 के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने 12 मई, 1993 तक माल की आपूर्ति की जिसका अर्थ है कि उसके बाद किसी भी माल की आपूर्ति नहीं की गई। इस स्थिति में, मैं यह समझने में विफल हूं कि कौन सी असाधारण परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण एकतरफा आदेश पारित किया गया। जब वादी 10 जून, 1993 के सेटर को चुनौती देने के लिए लगभग 2 महीनों तक प्रतीक्षा कर सकता था, तो अदालत याचिकाकर्ता-कंपनी को विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की सूचना दिए जाने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकती थी। विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन पर, मैं पाता हूं कि उसने न तो प्रशंसनीय कारण दिए हैं और न ही सभी सुसंगत कारकों पर विचार किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि यदि एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जाता है तो निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य स्वयं कैसे विफल हो जाएगा। निचली अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि इस अदालत का सहमति वाला दृष्टिकोण यह है कि जहां नोटिस जारी करने में देरी से निषेधाज्ञा का उद्देश्य विफल हो जाएगा, उसके अलावा पक्षकार को नोटिस का आदेश दिया जाना चाहिए, उसके खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश दिए जाने से पहले।

(6) अब, आक्षेपित आदेश के गुणागुण पर आते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिन्होंने अपील में विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की, ने मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया कि नियुक्ति समय के प्रभाव से समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता-कंपनी ने प्रत्यर्थी-फर्म को उनके आदेशों के विरुद्ध 12 मई, 1993 तक आपूर्ति की थी। इसके अलावा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अनुसार, यदि वादी की नियुक्ति अनंतिम और 31 मार्च, 1993 तक वैध थी, तो याचिकाकर्ता-कंपनी को प्रत्यर्थी-फर्म को अधिकृत विक्रेता मानते हुए प्रत्यर्थी-फर्म के आदेश के खिलाफ कोई और आपूर्ति नहीं भेजनी चाहिए थी। चूंकि आपूर्ति 31 मार्च, 1993 के बाद की गई थी, इसलिए यह अनुमान लगाया गया था कि डीलरशिप को बढ़ाया गया था और नियुक्ति पत्र के खंड 10 के अनुसार 30 दिनों का नोटिस देकर ही इसे समाप्त किया जा सकता था। एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश की पुष्टि करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को इस कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनतिम थी और 31 मार्च, 1993 तक वैध थी। 13 अक्टूबर, 1992 के पत्र के तहत, नियुक्ति की समीक्षा प्रतिवादी फर्म के प्रदर्शन के अधीन आगे की अवधि के लिए की जा सकती है। खंड 10 के तहत, डीलरशिप को बिना कोई कारण बताए 30 दिनों के नोटिस के भीतर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। 10 जून, 1993 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता-कंपनी ने प्रतिवादी-फर्म की डीलरशिप को समाप्त कर दिया। अपने पत्र में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने कहाः "उपरोक्त नियुक्ति पत्र के खंड 10 के अनुसार आपकी डीलरशिप समाप्त हो गई है।"

यह याचिकाकर्ता कंपनी पर था कि वह प्रतिवादी-फर्म के प्रदर्शन की समीक्षा करे और यह याचिकाकर्ता-कंपनी थी जो या तो डीलरशिप का विस्तार कर सकती थी या उसे समाप्त कर सकती थी। 13 अक्टूबर, 1992 के पत्र में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता-कंपनी डीलरशिप की अवधि बढ़ाने के लिए किसी भी दायित्व के तहत थी। एक बार जब याचिकाकर्ता-कंपनी ने डीलरशिप को समाप्त करने का निर्णय लिया, तो अदालतों के लिए प्रतिबंध का आदेश पारित करना खुला नहीं था क्योंकि यह एक समझौते को लागू करने के बराबर होगा जो लागू करने योग्य नहीं था। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस बात की सराहना नहीं की है कि विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कुछ अनुबंध प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिनमें से एक खंड (ग) एक अनुबंध है जो अपनी प्रकृति में निर्धारणीय है। 'निर्धारणीय' शब्द का अर्थ है जिसे समाप्त किया जा सकता है निर्धारण किसी वस्तु को समाप्त करना है, खंड (ग) यह अधिनियमित करता है कि अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यदि यह अपनी प्रकृति में निर्धारणीय है। विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41, खंड (ई) में यह प्रावधान है कि किसी अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, जिसके निष्पादन को विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, यदि वादी एक अनुबंध को लागू नहीं कर सकता है जो निर्धारित करने योग्य है, तो प्रतिवादी को इसे समाप्त नहीं करने से कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए कि डीलरशिप को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था, तब भी कानूनी रूप से, डीलर हर्जाने का दावा कर सकता है लेकिन किसी भी मामले में

डीलरशिप को बहाल नहीं किया जा सकता है। डीलरशिप स्वाभाविक रूप से कानून में समाप्त करने योग्य है और आम तौर पर डीलरशिप को समाप्त करने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव प्रारंभिक चरण में मुकदमे का आदेश देना होगा।

(7) मैं प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस तर्क से भी सहमत नहीं हूं कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा 31 मार्च, 1993 के बाद कंपनी को माल की आपूर्ति करने के बाद डीलरशिप जारी रखी गई मानी जाएगी। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डीलरशिप की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपने आचरण से, डीलरशिप को जारी रखने का आभास दिया है। लिखित कथन में याचिकाकर्ता-कंपनी का निश्चित रुख यह था कि 31 मार्च, 1993 से पहले दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया गया था , केवल उन्हीं विद्युत/ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति की गई थी जिनके लिए 31 मार्च, 1993 से पहले ऑर्डर दिए गए थे। याचिकाकर्ता-कंपनी के इस रुख को ध्यान में रखते हुए, यह मान लेना गलत था कि डीलरशिप को इस तथ्य के बावजूद बढ़ाया गया था कि याचिकाकर्ता-कंपनी या इस संबंध में किसी भी दस्तावेज द्वारा इस आशय का कोई पत्र कभी जारी नहीं किया गया था। इन सभी कारणों से, मेरा विचार है कि निम्नलिखित न्यायालयों ने निषेधाज्ञा देते समय अपनी अधिकारिता के प्रयोग में भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया और उस मामले के लिए आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(8) निष्कर्ष निकालने से पहले मुझे श्री एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील-न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कंपनी के एक अन्य तर्क पर ध्यान देना चाहिए। उनका तर्क था कि रोहतक में दीवानी अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि सभी विवाद जयपुर न्यायशास्त्र के अधीन थे। इसके लिए, उन्होंने (i) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम अमृतसर गैस सर्विस और अन्य (1991 (1) एस सी.सी. 533) (ii) हाकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड, (ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 740.) का उल्लेख किया। लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम ए. पी. एजेंसियां, सलेम (ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1239.).

(9) यह सत्य है कि 'पत्र' के खंड 8 में यह उपबंध है कि नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद जयपुर अधिकारिता के अधीन होंगे, लेकिन मैं इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न पर निर्णय लेने का इरादा नहीं रखता क्योंकि इसके लिए कुछ साक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसका नेतृत्व पक्षकारों ने अभी तक नहीं किया है। निस्सन्देह, यह विचारण न्यायालय पर होगा कि वह न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में मुद्दा तैयार करे, जिस पर पक्षकारों के अभिवचनों से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य मुद्दे का निर्धारण करने से पहले निर्णय दिया जाएगा।

(10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस नागरिक संशोधन की अनुमति लागत के साथ दी गई है। निम्नलिखित न्यायालयों के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है। शुलक के 2000 रुपये तय किए है ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा मेंअनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा